[श्री सरजू पाण्डेय]

जैसे ग्रन्य विश्वविद्यालयों में शिक्षा देने की व्यवस्था है व डिग्रियां प्रदान करने की व्यवस्था है वह सारी व्यवस्था इस में भी की जाय। इस के लिए मैं चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री महोदय इस सदन् के सामने एक ऐसा सम्पूर्ण बिल लायें जोकि सही मायनों में नेहरू जी की भावनाओं से ओतप्रोत हो और जिससे कि देश के गरीब छात्रों को सस्ती और उत्तम शिक्षा सुलभ हो सके। इसलिए इस बात की नितान्त आवश्यकता है कि यह जो विश्वविद्यालय आप बनाने जा रहे हैं उसके लिए बिल में आवश्यक तब्दीलियां होनी चाहिएं। संयुक्त समिति मुझे आशा है कि पूरे तौर पर इन सब बातों पर विचार करके इसको सुधारेगी तभी सही मायनों में यह एक अच्छी युनिवरसिटी यहां पर हम बना सकते हैं।

15.31 hrs.

STATEMENT RE: CHINESE ULTIMATUM

Mr. Speaker: The hon. Prime Minister—

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद): अध्यक्ष महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान संविधान की धारा 105 की तरफ खींचता हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : इस वक्त कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

डा० राम मनोहर लोहिया : जब प्रधान मंत्री महोदय अपनी बात बोल लेंगे उसके बाद हम में से कोई न तो अपनी बात बोल पायेगा न ही सवाल पूछ पायेगा। नतीजा यह होगा कि केवल उनकी वाणी की स्वतंत्रता होगी हममें से किसी की नहीं होगी जो कि धारा 105 के बिलकुल खिलाफ जाता है। मैं आप को संविधान की धारा 105 पढ़ कर सुनाता हूं। मुझे स बदकिस्मत धारा अंग्रेजी में पढ़ने के लिए माफ़ किया जाय क्योंकि संविधान अंग्रेजी में है। धारा 105 यह है :—

> "Subject to the provisions of this Constitution and to the rules and standing orders regulating the procedure of Parliament there shall be freedom of speech in Parliament."

यह संविधान की धारा है। अब यह फ्रीडम ऑफ़ स्पीच हम इस सत्र में बिलकुल नहीं इस्तेमाल कर पाये हैं। बड़े बड़े मसले जो आये हैं चाहे वह भारत पाक का झगड़ा हो, चाहे चीन वाला हो, वह केवल प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री इस्तेमाल कर पाये हैं। अब मिसाल के लिए जब पाकिस्तान ने छम्ब, जोरियां और अखनूर पर हमला किया......

अध्यक्ष महोदय : उस का क्या ताल्लुक है ?

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं एक मिसाल तो दे दूं। उस को विफल बनाने के लिए हिन्दुस्तान की पलटनें लाहौर और सियालकोट गईं। अब चीन ने उसी तरीके से हमले की धमकी दी है तो मेरा जैसा आदमी यह कहना चाहता कि हमला होने के बाद पेकिंग के इस जंगली जानवर को तिब्बत की गुफाओं में ढूंढ कर खत्म कर देना चाहिए लेकिन वह बात तभी कही जा सकती है जब कि आप हम को इस बात की इजाजत दें। आपने उस दिन जो मुझे पढ़ कर सुनाया था प्रक्रिया वाला नियम, वह इसलिए लागू नहीं होता कि एक तो धारा 105 को खत्म करने वाला नियम खराब होता है दूसरे जब भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हम लोगों की तरफ से दिया जाता है और उस के जवाब में मंत्री अपना बयान देते हैं तो वह धारा नहीं लागू हो सकती है जो धारा कि आपने पढ़ कर सुनाई थी। तीसरे इसलिए कि अगर उस धारा को हमेशा इस्तेमाल करके हमारी वाणी की स्वतंत्रता को खत्म करते रहेंगे तो

फिर लोक-सभा का कोई महत्व नहीं रह जायगा।

अध्यक्ष महोदय : वह ध्यानाकर्षण नोटिस के ऊपर अपना बयान नहीं दे रहे थे बल्कि वह बयान अपने आप दे रहे थे। ध्यानाकर्षण नोटिस कोई सामने नहीं था इस वास्ते वह सवाल करने का कोई मौका नहीं था।

एक दूसरी बात यह कि यहां फ्रीडम आफ़ स्पीच हो तो यहां पर वाक़ई यह फ्रीडम आफ़ स्पीच है मगर वह रैगुलेटेड है वह एक फ्री लाइसेंस की मानिन्द नहीं है कि जब भी आदमी चाहे खड़ा हो जाय और उठ कर बोलना शुरू कर दे। अब इस फ्रीडम आफ़ स्पीच से क्या यह समझा जाय कि डाक्टर साहब बोलते चले गये और मैं उसे सुनता चला गया? अगर उनके नजदीक यही फ्रीडम आफ़ स्पीच है तो भी उन्होंने जो कुछ कहना था वह कह लिया है। इस बारे में जो रूल्स आदि बने हैं मैंने उस दिन भी उन्हें पढ़ कर सुनाया था। इस वक्त जो वह स्टेटमैंट देंगे उस पर कोई इसी वक्त बहस नहीं हो सकती है। दूसरा रहा सवाल उनका किसी डिस्कशन के उठाने का, बहस करने का, तो कोई बहस यहां नहीं हो सकती, जब तक कि उसकी बाबत पहले कोई मोशन न हो। मैम्बर को मोशन लाना पड़ता है तब ही कोई बहस हो सकती है। ऐसे नहीं हो सकता है। इस वास्ते इन के स्टेटमैंट पर चाहे गवर्नमैंट कोई मोशन लाये चाहे प्राइवेट मैम्बर लाये, स्पीकर जब उस को मंजूर कर लेगा तभी कोई डिस्कशन हो सकता है वैसे कोई डिस्कशन नहीं हो सकता है। इस के सिवाय और कोई क़ायदा नहीं है।

डा० राम मनोहर लोहिया : अब प्रस्ताव लाने के लिए तो आप मुझे एक बार निकाल चुके हैं। इस पूरे सत्र में आप ने किसी को स्वतंत्रता नहीं दी सिवाय प्रधान मंत्री के और रक्षा मंत्री के, तो यह कौन सा क़ायदा, कानून है?

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri): Mr. Speaker, Sir, I place on the Table of the House the text of a further note which was handed over to our Charge d'Affaires in Peking yesterday. [*Placed in Library. See* No. LT-4904/65].

The House will recall that we had taken an attitude calculated to maintain peace when replying to the last note which we had received from the Chinese Government. It is clear from the kind of response which China has sent that what China is looking for is not a redress of grievances, real or imaginary, but some excuse to start its aggressive activities again, this time acting in collusion with its ally, Pakistan. (*Shri Frank Anthony:* Shame.) The extension of the time-limit for the ultimatum was in our view, no more than a device to gain time to watch what comes out of the discussions in the Security Council.

The allegations which China has been making in the series of notes that it has been sending to us, are such that they would hardly justify any civilised Government in having recourse to force, even if the allegations were true. If there are any structures on Chinese territory in areas where the border is delimited and not in dispute even according to the Chinese, surely, there is nothing to prevent the Chinese Government from having them removed, instead of suggesting to us that we should have them removed, which would only be possible by our men going into their territory. Similarly no one can imagine that any Government would threaten another on the ground that their cattle have been lifted or on the ground that out of the thousands of Tibetans who have sought asylum in this country two or four are being detained here against their wishes.

To justify its aggressive attitude, China is pretending to be a guardian of Asian countries who, according to China, are being bullied by India. The basic objective of China, therefore, is

[Shri Lal Bahadur Shastri]

to claim for itself a position of dominance in Asia which no self-respecting nation in Asia is prepared to recognise. Large or small, strong or weak, every country in Asia has the fullest right to preserve its independence and sovereignty on terms of equality. The dominance of the Chinese cannot be accepted by any of them. We reject China's claim to tell us anything about what we should or should not do about Kashmir which is an integral part of India. Our offer of resolving the differences over these minor matters by peaceful means is still open.

However, China's aggressive intentions are clear from the fact that even while they have in their note extended the time-limit by 72 hours, in actual fact they have started firing at our border posts both in Sikkim and in Ladakh.

Shri Nath Pai (Raipur): Fire back.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Fire back.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): Reply to the fire.

Shri Lal Bahadur Shastri: If, China persists in aggression, we shall defend ourselves by all means at our disposal.

A formal reply to the Chinese note will be sent later today.

May I say a word that we have just now received the full text of the resolution passed in the Security Council? Naturally it deserves our very careful consideration, and I might be making a statement on that tomorrow in the House.

Shri Nath Pai: I am not putting a question, Sir. He said that the Chinese have started firing across the frontier. We want to know whether we are going to be just content with the sending of a note or that the orders to the Indian army are, "If they fire, you fire back." This must be clarified. Sir, you should not try to stall this clarification. We have been extremely cooperative and patient. We do not want to wait till tomorrow to know something from the press. We want to know it from the Prime Minister. He is replying to it.

Shri Lal Bahadur Shastri: I would merely like to say that we will resist them and we will fight them . . .

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक बात । जिस तरह से हमारी सेनायें स्यालकोट और लाहौर गई हैं, उसी तरह क्या वे पीकिंग के जानवर का पीछा करने तिब्बत की गुफाओं में भी जायेंगी या नहीं ? प्रधान मंत्री इस का जवाब दें । हंसने से काम नहीं चलेगा । वह जवाब दें । (*Interruptions*).

15.41 hrs.

JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY BILL—*contd.*

Mr. Speaker: We will now take up the further consideration of the Bill that was under discussion earlier. Shri Sheo Narain.

श्री शिव नारायण (बांसी) : अध्यक्ष महोदय, मैं जवाहरलाल विश्वविद्यालय विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं डा० लोहिया को कहूंगा कि वह मेरी बात सुनें ।

हमारी भारतीय संस्कृति का मूल सिद्धान्त और आधार यह है :

मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्,
आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः

मैं आशा करता हूं कि इस नये विश्वविद्यालय में हमारे इस मूल सिद्धान्त का ख्याल रखा जायेगा । जहां तक इस विश्वविद्यालय